बिहार सरकार
उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना।

पत्रांक....................../   पटना, दिनांक................
सं0सं0-05/उ0नि0 गणना-04/19

प्रेषक :-

उद्योग निदेशक,
बिहार, पटना।

सेवा में,

महाप्रबंधक,
सभी जिला उद्योग केन्द्र
बिहार

विषय :- 7th Economic Census हेतु जिला स्तरीय समन्वय समिति के गठन के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक योजना एवं विकास विभाग, अर्थ एवं संख्यिकी निदेशालय के अधिसूचना संख्या-490 दिनांक-06.05.19 की छायाप्रति संलग्न करते हुए कहना है कि संख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार के निदेशानुसार राज्य में सातवी आर्थिक गणना के त्वरित संचालन एवं उत्पन्न कठिनाईयों के निराकरण हेतु जिला स्तरीय समन्वय समिति का गठन किया गया है। गठित जिला स्तरीय समन्वय समिति के कम संख्या-iii पर महाप्रबंधक जिला उद्योग केन्द्र के प्रतिनिधि को सदस्य नामित किया गया है। वर्णित पत्र में समिति के कार्यो का भी उल्लेख किया गया है।

उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना के पत्रांक-1917, दिनांक-07.05.19 द्वारा संख्यिकी एवं कार्यकम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा किये जा रहे 7th Economic Census में अपेक्षित सहयोग करने हेतु आपको निदेशित किया जा चुका है।

अनु0 :- यथोक्त।

विश्वासभाजन,

ह0/-
उद्योग निदेशक,
बिहार, पटना।

ज्ञापांकः- *सं0सं0-05/उ0नि0 गणना-04/19*   पटना, दिनांक........................

प्रतिलिपिः- अपर सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना को उनके अधिसूचना संख्या-आ0ग0-01/2019-490 दिनांक- 06.05.19 के आलोक में सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/-
उद्योग निदेशक,
बिहार, पटना।

ज्ञापांकः- *सं0सं0-05/उ0नि0 गणना-04/19* 1989 पटना, दिनांक 21.5.19

प्रतिलिपिः- आई0टी0 मैनेजर, उद्योग विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

उद्योग निदेशक,
बिहार, पटना।

D:\Rahul_Work-Directorates Of Industries\Udyog Nideshalay\Section-4(iii)

बिहार सरकार
उद्योग निदेशालय

पत्रांक 1917/ पटना, दिनांक 07.05.19
सं0 सं0–05/उ0 नि0 गणना 04/2019

प्रेषक,

उद्योग निदेशक,
बिहार, पटना।

सेवा में,

महाप्रबंधक,
सभी जिला उद्योग केन्द्र, बिहार।

विषय : 7th Economic Census **में सहयोग करने के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 7th Economic Census का कार्य पूरे देश में किया जा रहा है। श्री रमेश अभिषेक, सचिव, औद्योगिक नीति और संवर्द्धन विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, उद्योग भवन, नई दिल्ली–110011 के अर्द्धसरकारी पत्र सं0 P49019/2/2018-ISU दिनांक 19.12.2018 द्वारा इस वृहत कार्य में राज्यों के उद्योग विभाग के प्रधान सचिव से सहयोग करने का अनुरोध किया गया है।

अतः वर्णित पत्र के आलोक में निदेश दिया जाता है कि सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा किये जा रहे 7th Economic Census में अपेक्षित सहयोग करना चाहेंगे।

विश्वासभाजन

6/5
उद्योग निदेशक,
बिहार, पटना।
6.5.19

बिहार सरकार
अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय
(योजना एवं विकास विभाग)

संचिका संख्या–आ०ग०–01 / 2019 440

पटना, दिनांक 6.5.19

अधिसूचना

सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार के निदेशानुसार राज्य में सातवीं आर्थिक गणना के त्वरित संचालन एवं उत्पन्न कठिनाईयों के निराकरण हेतु जिला स्तरीय समन्वय समिति का गठन निम्न प्रकार किया जाता है –

(ख) जिला स्तर पर समन्वय समिति

(i)	जिला पदाधिकारी	अध्यक्ष
(ii)	जिला परिषद के प्रतिनिधि	सदस्य
(iii)	महाप्रबंधक जिला उद्योग केन्द्र के प्रतिनिधि	सदस्य
(iv)	National Sample Survey Office (NSSO) Field Operation Division (FOD) के प्रतिनिधि	सदस्य
(v)	जिला सूचना पदाधिकारी	सदस्य
(vi)	जिला सांख्यिकी पदाधिकारी	सदस्य सचिव

<u>जिला स्तरीय समन्वय समिति (**Distric Level Coordination Committee**) द्वारा सातवी आर्थिक गणना के लिए किये जानेवाले कार्य इस प्रकार है:–</u>

(1) जिले में सातवीं आर्थिक गणना की तैयारी, प्रगति और बाधाओं का नियमित समीक्षा।

(2) जिला स्तर पर अपनी भूमिकाओं और कार्यो को प्रभावी ढंग से करने के लिए राज्य स्तरीय समन्वय समिति की सहायता करना।

(3) आर्थिक गणना के सुचारू संचालन के लिए CSC(Common Service Center)-SPV(Special Purpose Vehicle) की मदद करने के लिए स्थानीय प्रशासन और पंचायत को संवेदनशील / निर्देशित करना

(4) आर्थिक गणना को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए Common Service Center (CSC) - Special Purpose Vehicle (SPV) को नगर निकायों का वार्डवार मानचित्र और ग्रामीण क्षेत्रों का ग्राम पंचायतवार मानचित्र संबंधित प्राधिकारों से प्राप्त करना।

(5) State Level Coordination Committee (SLCC) को फीडबैक प्रदान करना।

(6) आर्थिक गणना की जिला स्तरीय रिपोर्ट का अनुमोदन और प्रसार करना।

बिहार के राज्यपाल के आदेश से,

अपर सचिव
योजना एवं विकास विभाग
बिहार, पटना

adhisuchana-ec

ज्ञापांक: 490 /पटना, दिनांक– 06.05.19

प्रतिलिपि:– अधीक्षक सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग पटना को राजपत्र के असाधारण अंक में (हिन्दी एवं अंग्रेजी प्रारूप) प्रकाशनार्थ प्रेषित।

अनुरोध है कि प्रकाशित राजपत्र की अतिरिक्त 50(पचास) प्रतियाँ निदेशक, अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार पटना को आवश्यक कारवाई हेतु भेजी जाए।

अपर सचिव
योजना एवं विकास विभाग

ज्ञापांक 490 /पटना दिनांक– 06.05.19

प्रतिलिपि:– 1. मुख्य सचिव, बिहार
2. प्रधान सचिव, उद्योग विभाग बिहार पटना।
3. प्रधान सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना।
4. प्रधान सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार पटना।
5. निदेशक,Micro small & medium Enterprises(MSME)Development Institute (DI), बिहार, पटना
6. उप महानिदेशक, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, National Sample Survey Office (NSSO) Field Operation Division (FOD), बिहार, पटना।
7. प्रधान सचिव/सचिव, योजना एवं विकास विभाग (राज्य नोडल पदाधिकारी) बिहार, पटना।
8. निदेशक, अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार, पटना।
9. संयुक्त निदेशक (प्रशासन) प्रभारी आर्थिक गणना, अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार, पटना।
10. सभी जिला पदाधिकारी, बिहार।
11. सभी जिला परिषद के प्रतिनिधि
12. सभी जिला उद्योग केन्द्र के प्रतिनिधि
13. National Sample Survey Office (NSSO) Field Operation Division (FOD)के प्रतिनिधि
14. सभी जिला सूचना पदाधिकारी, बिहार
15. सभी जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, बिहार

अपर सचिव
योजना एवं विकास विभाग

ज्ञापांक– 490 /पटना, दिनांक– 06.05.19

प्रतिलिपि:– सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव एवं सभी विभागाध्यक्ष को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अपर सचिव
योजना एवं विकास विभाग

ज्ञापांक– 490 /पटना, दिनांक– 06.05.19

प्रतिलिपि:– सभी प्रमण्डलीय आयुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अपर सचिव
योजना एवं विकास विभाग

ज्ञापांक– 490 /पटना, दिनांक– 06.05.19

प्रतिलिपि:– सभी प्रमण्डलीय उप निदेशक (सांख्यिकी)/सभी जिला सांख्यिकी पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अपर सचिव
योजना एवं विकास विभाग